
कांग्रेस और भाजपा द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए योजना

HIMANSHU PAPNAI

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और आज भारत कृषि के क्षेत्र में नई-नई उपलब्धि कर रहा है कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार भी नई-नई योजना निकाल रही है इन योजनाओं से किसानों को लगातार फायदा हो रहा है इन योजना के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़िए।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना =इस योजना को भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था हर किसान परिवार को 6000 सालाना की सहायता। इसमें तीन लाख से ज्यादा महिला किसानों को सीधा फायदा पहुंचा

DBT के जरिए रकम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है

2=महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना=ग्रामीण महिलाओं को खेती पशुपालन और जैविक खेती में ट्रेनिंग और सहायता अब तक 36 लाख से ज्यादा महिलाएं इसे जुड़ गई हैं

3=नमो ड्रोन दीदी योजना =15000 महिलाओं ड्रोन दिए जा रहे हैं ताकि वह ड्रोन चलकर खेत में फर्टिलाइजर अन्य चीज डाल सके

4=पीएम कुसुम योजना=किसानों को सोलर पंप देने की योजना ताकि किसान अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सके. और बिजली खर्च घाटे

महिला SHGs के लिए विशेष ऋण सहायता =किसानों को अपना व्यापार खोलने के लिए कर्ज दिया जा रहा है और महिलाओं को अपने व्यापार से जोड़ने के लिए यह योजना को शुरू किया गया

कांग्रेस सरकार ने भी समय समय पर कई योजनाएं निकाली

राजीव गांधी किस न्याय योजना (छत्तीसगढ़)

किसानों के खाते में सीधे सहायता राशि दी जाती है और किसानों को प्राथमिकता भी दी गई है हर साल हजारों महिलाओं को सीधे इसका लाभ मिलता है

मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना =मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी महिलाओं को सीड ,फर्टिलिजर सिंचाई ट्रेनिंग में सब्सिडी दी गई

गृह लक्ष्मी योजना (कर्नाटक)

हर महिला को ₹2000 मासिक सहायता ताकि वह घरेलू और फसल उगा सके।

इंदिरा गांधी महिला किसान कल्याण निधि =महिला किसानों के लिए क्या योजना शुरू की गई है जिसमें खाद और बीज में अतिरिक्त सहायता दी जाती है

SHG सशक्तिकरण कार्यक्रम=कांग्रेस शासन शासित प्रदेश में महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है इन योजनाओं का मतलब है महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक पहचान दिलाना.

योजनाओं की जमीन हकीकत क्या है

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 75% ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हैं लेकिन सिर्फ 13 प्रतिशत के पास मालिन का ना हक है मतलब जो खींच मरती हैं वह कागज में मालिकाना हक नहीं नहीं मिलता है जिसके कारण वह परेशान हो जाती हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के भी उनके पास पैसे नहीं होती।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और आज भारत कृषि के क्षेत्र में नई-नई उपलब्धि कर रहा है
